an>

Title: Need to grant financial assistance to Uttarakhand to protect environment in accordance with geographical requirements and also rehabilitate people affected due to natural calamities and present forest laws in the State.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) ः जैव विविधता के क्षेत्र में हिमालय पूरे विश्व में सबसे वैविध्य वाले क्षेत्रों में आता है। पूरे देश का भौगोलिक क्षेत्र 3,287,240 वर्ग कि.मी. है, जिसमें दुनिया के चार हॉट स्पॉटों में से एक हिमालय में स्थित है। विश्व के 130 करोड़ लोग हिमालीय संसाधनों और अपवाह पर निर्भर हैं। उत्तराखण्ड में कुल वन क्षेत्र 24,508 वर्ग कि.मी. है जिसमें सैंकड़ों हिमनद गंगा और यमुना सहित अनेक नदियों को जन्म देते हैं। साढ़े बारह हज़ार वन पंचायतों में ढ़ाई लाख से अधिक नागरिक तमाम खतरों का सामना करते हुए अपने निजी वनों को सुरक्षित रखते हैं। अपने सीमित संसाधनों में भी लोग बच्चों से ज्यादा वनों की चिंता करते हैं। विश्वविख्यात चिपको आन्दोलन के प्रेरणास्रोत श्रीमती गौरा देवी और चण्डी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा भी उत्तराखण्ड से संबंध रखते हैं। आज हमारे किसानों एवं नागरिकों को जहां एक ओर प्रकृति की मार झेलनी पड़ रही है वहीं वन्यजीवों से क्षेत्र के किसानों की खेती पूरी तरह से चौपट हो गयी है। वन्यजीव आये दिन किसानों की फसलों को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं साथ ही लोगों पर हमले भी करते हैं जिससे कई लोग अपनी जान भी गवां चुके हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वनों से आच्छादित इस क्षेत्र में क्षेत्रीय परिस्थितिकी के अनुकूल विकास हेतु अलग से योजना का प्रावधान ग्रीन बोनस के रूप में किया जाये ताकि वनों से प्रभावित या उन पर आश्रित लोग गांवों में पलायन न करें, साथ ही जंगली जानवर संरक्षण नियमों को तर्कसंगत एवं व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भीषण आपदाओं और वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के तहत जो गांव पूरी तरह इससे प्रभावित होकर पुनर्वास की बांट जो रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा पुनर्वासित किया जाये।